3

कमलनाथ की खनिज नीति कर रही आकर्षित

5
जनकल्याण के लिए समर्पित रहे हैं दादाभाई

6
सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 26 | प्रति सोमवार, 03 नवंबर 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश के 70 वर्ष

विकास, विरासत और भविष्य की राह

विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में अग्रसर मध्यप्रदेश

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

01 नवम्बर 1956 को जब मध्यप्रदेश का गठन हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह भू-भाग आने वाले दशकों में "भारत का दिल" कहलाएगा। न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से भी। आज 1 नवम्बर 2025 को जब मध्यप्रदेश अपना 70वाँ स्थापना दिवस मना रहा है, तब यह अवसर आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने का है। स्वतंत्रता के बाद देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग तेज हुई। उसी प्रक्रिया के तहत 1 नवम्बर 1956 को States Reorganisation Act के तहत मध्यप्रदेश का गठन हुआ। उस समय मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोजपुर राज्य को मिलाकर नया

राज्य बना। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना, और आज का मध्यप्रदेश अपने लगभग 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 52 जिलों के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्यप्रदेश की पहचान उसकी सांस्कृतिक बहुलता और भौगोलिक विविधता से है। यहाँ की धरती नर्मदा, बेतवा, चंबल और ताप्ती जैसी नदियों से सिंचित है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों की गोद में बसे जंगलों में जैव विविधता की अपार संपदा है।

राज्य का हर क्षेत्र चाहे मालवा की कला-संस्कृति, बुंदेलखंड का शौर्य, महाकौशल का ज्ञान या गोंडवाना का जनजीवन अपने आप में विशिष्ट है। उज्जैन, खजुराहो, सांची और अमरकंटक जैसे स्थल न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर मध्यप्रदेश की पहचान भी हैं। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप पर आगे बढ़ रहा राज्य

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करते हुए विकास यात्रा का नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप तय किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में प्रदेश की जीडीपी को दोगुना कर 75 लाख करोड़ तक पहुँचाना है, जिससे प्रत्येक नागरिक की आय में दस गुना वृद्धि हो सके। नई

उद्योग नीति ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। अब तक लगभग 6.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्राथमिकता दी गई है। एमएसएमई स्टार्टअप और नई टेक्नॉलॉजी आधारित उद्योगों को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। कोरबा जिले के पॉवर एवं मेटल सेक्टर से लेकर दुर्ग-राजनांदगांव के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक नए औद्योगिक केंद्र विकसित हो रहे हैं। (शेष पेज 7 पर)

इंदौर की घटना बनी राजनीति का नया मैदान; महिला सुरक्षा बनाम राजनीतिक बयानबाज़ी का खेल

(विस्तृत पेज 2 पर)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की खनिज नीति निवेशकों को कर रही आकर्षित, खनिज कॉन्क्लेव में 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त

कमलनाथ की दूरदृष्टि का मध्यप्रदेश को मिल रहा लाभ

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में खनिज विभाग की नीति को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जिस खनिज नीति को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 18 माह के कार्यकाल में तैयार करवाया था, वही आज प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में आयोजित खनिज कॉन्क्लेव में 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह न केवल राज्य के खनिज क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि कमलनाथ सरकार द्वारा तैयार की गई नीति की जड़ें अब भी प्रभावी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को आकर्षित करने की जो बुनियाद कमलनाथ सरकार ने रखी थी वही आज इस उपलब्धि का कारण बनी है। वर्तमान सरकार भी इस बात को नकार नहीं सकती कि नीति ढाँचा वही है, जो 2020 में कांग्रेस शासनकाल में लागू हुआ था। यह इस बात का प्रमाण है कि नीति अगर दूरदर्शिता से बनाई जाए तो उसका लाभ वर्षों बाद भी मिलता है।

कमलनाथ की सोच निवेशक केंद्रित नीतियों की नींव

कमलनाथ का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव सदैव व्यावहारिकता पर आधारित रहा है। जब वे 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने सबसे पहले प्रदेश की नीतिगत व्यवस्था की समीक्षा करवाई। (शेष पेज 3 पर)

इंदौर जिसे देश स्वच्छता की राजधानी के रूप में जानता है आज एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण से सुर्खियों में है

पुलिस प्रशासन और सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की विफलता है यह घटना

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है कैलाश विजयवर्गीय का बयान

-विजया पाठक

क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ हुई अभद्रता ने न केवल खेल भावना को आहत किया है बल्कि इसने मध्यप्रदेश की छवि और पुलिस व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो घटना खेल के मैदान से जुड़ी होनी चाहिए थी वह अब राजनीति के अखाड़े में परिवर्तित हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप मैच के बाद इंदौर के एक बाजार में पहुंची थीं जहाँ कुछ युवकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मामला जैसे ही सामने आया प्रदेश का माहौल गर्मा गया। पुलिस ने पहले तो घटना को छोटी गलतफहमी बताकर टालने की कोशिश की लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने यह साफ कर दिया कि घटना गंभीर है और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोटोकॉल के तहत होती है तो आखिर एक विदेशी महिला खिलाड़ी कैसे बिना सुरक्षा घेरे के खुले बाजार तक पहुंच गई। क्या यह पुलिस प्रशासन की चूक थी या प्रोटोकॉल का उल्लंघन।

प्रशासनिक विफलता और लीपापोती की कोशिश

घटना के बाद पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया ने सवालों को और बढ़ा दिया। पहले तो पुलिस ने कहा कि खिलाड़ी अकेले नहीं थीं। बाद में कहा गया कि गलतफहमी हुई और जब मामला मीडिया में फैल गया तो लीपापोती शुरू हो गई। इंदौर पुलिस अब यह साबित करने में लगी है कि घटना उतनी बड़ी नहीं जितनी दिखाई जा रही है"परंतु प्रश्न यह नहीं है कि घटना कितनी बड़ी थी। प्रश्न यह है कि ऐसी घटना हुई क्यों। प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेषकर महिला सुरक्षा के प्रति सरकार के दावे इस एक घटना से कमजोर होते दिखे हैं।

राजनीति ने पकड़ा तूल

मामला और भी गरम तब हुआ जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा था ऐसी घटनाएँ राज्य की छवि को धूमिल करती हैं। इसलिए पुलिस को और सतर्क रहना चाहिए। उनका यह बयान राज्य की छवि को लेकर चिंता का प्रतीक था। लेकिन कांग्रेस ने इसे महिला खिलाड़ी के प्रति असंवेदनशीलता बताकर राजनीतिक रंग दे दिया। बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और सोशल मीडिया पर इसे महिला विरोधी टिप्पणी के रूप में प्रचारित किया गया। राजनीति के इस नए मोड़ ने मुद्दे को पूरी तरह महिला सुरक्षा से हटाकर बयानबाजी की लड़ाई में बदल दिया। जहां एक ओर भाजपा नेता यह कह रहे हैं कि विजयवर्गीय का आशय प्रशासन की लापरवाही को इंगित करना था वहीं कांग्रेस ने इसे राज्य सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही से जोड़ दिया।

खेल सुरक्षा और जिम्मेदारी

यह कोई पहला मौका नहीं है जब महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना घटी हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लंदन| सिडनी| जोहान्सबर्ग और दिल्ली जैसे शहरों में विदेशी महिला खिलाड़ियों या पर्यटकों के साथ अभद्रता की घटनाएँ हो चुकी हैं। परंतु जब ऐसा किसी खेल आयोजन से जुड़े व्यक्ति के साथ होता है तो इसका प्रभाव केवल स्थानीय नहीं रहता बल्कि देश की वैश्विक छवि और खेल कूटनीति पर भी पड़ता है। इंदौर में घटी यह घटना भारत के लिए एक कूटनीतिक और छवि-संबंधी चुनौती बन सकती है। यह समय है जब भारत खेल पर्यटन और निवेश के माध्यम से ग्लोबल इमेज मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएँ सॉफ्ट पावर के लिए खतरा हैं।

व्यवहारिक संवेदनशीलता की आवश्यकता

सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं 108 महिला हेल्पलाइन महिला थाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और नारी शक्ति मिशन जैसी पहलें। फिर भी जब कोई विदेशी महिला खिलाड़ी बाजार में असुरक्षित महसूस करती है तो यह दर्शाता है कि प्रणालियाँ मौजूद तो हैं पर संवेदनशीलता का अभाव है। महिला सुरक्षा केवल कानून और हेल्पलाइन से नहीं आती वह आती है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन से और यही वह पहलू है जहाँ सरकार और समाज दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए।

संवेदनशील मुद्दे पर तुष्टिकरण नहीं समाधान आवश्यक

राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालें परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह घटना भी राजनीतिक लाभ के खेल में तब्दील हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया जहाँ एक पक्ष प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर रहा है तो दूसरा पक्ष बयान की गलत व्याख्या पर सफाई दे रहा है। इस बीच असली सवाल महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था कहीं गुम हो गया है।

इंदौर की पहचान स्वच्छता से संवेदनशीलता की ओर

इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सात बार देश का नाम रोशन किया है। अब आवश्यकता है कि वह सुरक्षा और संवेदनशीलता की राजधानी बने। यह तभी संभव है जब प्रशासनिक तत्परता के साथ-साथ नागरिक चेतना भी जागे। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा के विशेष प्रोटोकॉल बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करे।

खेल भावना की पुनर्स्थापना

इंदौर की यह घटना एक चेतावनी है कि महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सजगता किसी भी राज्य की छवि के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति मिशन के तहत महिला सम्मान और सुरक्षा के कई अभियान शुरू किए हैं परंतु इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से अधिक जरूरी है उसका पालन और क्रियान्वयन। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस घटना को राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का अवसर मानें। कैलाश विजयवर्गीय का बयान चाहे जिस रूप में लिया गया हो मूल मुद्दा यही है अगर एक विदेशी महिला खिलाड़ी हमारे देश में असुरक्षित महसूस करती है तो यह केवल सरकार की नहीं पूरे समाज की विफलता है।

विकास, विरासत और भविष्य की राह विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में अग्रसर मध्यप्रदेश

(पेज 1 का शेष)

1956 में जब राज्य बना, तब उसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। आज भी राज्य की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। परंतु पिछले दो दशकों में औद्योगीकरण, शहरीकरण और सेवाक्षेत्र के विस्तार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर अब औद्योगिक, आईटी और शिक्षा केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। इंदौर लगातार कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का नंबर-1 शहर रहा है, जो नगर प्रशासन और जनभागीदारी की मिसाल है।

राज्य में कृषि उत्पादन, विशेषकर सोयाबीन, गेहूँ और दालों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में नर्मदा घाटी परियोजना और विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं ने कृषि को स्थायित्व प्रदान किया है। हालाँकि आर्थिक विकास के साथ-साथ राज्य को सामाजिक मोर्चे पर अब भी लंबी दूरी तय करनी है। साक्षरता दर, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ और आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है। मध्यप्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या आदिवासी समुदायों से आती है— भील, गोंड, बैगा, कोरकू जैसे जनजातीय समूह यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा हैं। (शेष पेज 3 पर)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की खनिज नीति निवेशकों को कर रही आकर्षित, खनिज कॉन्क्लेव में 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त

(पेज 1 का शेष)

उन्होंने पाया कि खनिज विभाग समेत कई विभागों की नीतियाँ निवेशकों के दृष्टिकोण से जटिल और प्रक्रियात्मक रूप से भारी हैं। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में खनिज नीति को पूरी तरह से निवेशक उन्मुख बनाने की दिशा में काम किया। खदानों के लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया सरल की गई।

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रणाली लागू की गई

छोटे खनन उद्यमों के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ की गई और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय समुदायों की भागीदारी को नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया। कमलनाथ का मानना था कि "खनिज केवल आर्थिक संपदा नहीं, यह स्थानीय विकास का माध्यम भी है।" यही कारण था कि उन्होंने नीति में ग्राम पंचायतों और जिला खनिज फाउंडेशन को सशक्त करने पर जोर दिया।

18 माह में बिछाई गई वह मजबूत बुनियाद

कमलनाथ सरकार का कार्यकाल भले ही 18 माह का रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने खनिज, उद्योग, ऊर्जा, नगरीय विकास और कृषि जैसे प्रमुख विभागों की नीतियों में व्यापक सुधार किए। खनिज नीति के मामले में उन्होंने न केवल पारदर्शिता लाई, बल्कि निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश में खनन कारोबार अब "अनुमति आधारित भ्रष्टाचार" से मुक्त होगा। उन्होंने छोटे और मझोले खननकर्ताओं के लिए कई नियमों में ढील दी, जिससे राज्य में खनिज क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और राजस्व में वृद्धि हुई।

भाजपा शासनकाल की विफलताएँ और घोटाले

जहाँ कमलनाथ ने नीति में पारदर्शिता का प्रयास किया, वहीं पिछले 18 वर्षों के भाजपा शासनकाल में खनिज विभाग पर घोटालों, अनियमितताओं और आपराधिक घटनाओं के आरोप लगते रहे। राज्य के कई जिलों जैसे सागर, कटनी, दमोह, बालाघाट और छतरपुर में अवैध उत्खनन के मामले सामने आए। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक मिलीभगत के कारण न केवल राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हुआ। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण कटनी जिले का है, जहाँ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक पर खनिज विभाग को 453 करोड़ रुपए की चपत लगाने के आरोप लगे। यह केवल एक मामला नहीं है- यह उस व्यवस्था की पहचान है जिसमें खनिज विभाग "राजस्व सृजन" से अधिक "राजनीतिक कमाई" का माध्यम बन गया था।

खनिज विभाग की स्थिति अपराध और अराजकता

खनिज विभाग का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अवैध खनन प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौतियों में रहा है। पिछले 18 वर्षों में खनन माफिया के कारण कई जिलों में हिंसक घटनाएँ हुईं, अधिकारियों पर हमले, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या और ग्रामीणों के साथ मारपीट के मामले आम रहे। इन घटनाओं ने यह साबित किया कि जब तक नीति निवेशक केंद्रित और पारदर्शी नहीं होगी, तब तक विभाग विकास का नहीं, बल्कि विवाद का केंद्र बना रहेगा। कमलनाथ के 18 महीनों में ऐसी कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने नहीं आई। इसका कारण था कठोर नियंत्रण, जवाबदेही और सख्त निगरानी तंत्र।

खनिज नीति की दिशा और लाभ

कमलनाथ सरकार की खनिज नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें स्थायित्व और पारदर्शिता को समान महत्व दिया गया। राज्य के खनिज संसाधनों का दोहन नियंत्रित तरीके से हो, यह सुनिश्चित किया गया। नीति में यह भी प्रावधान था कि खनिज राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत स्थानीय विकास जैसे सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च किया जाए। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व को भी रेखांकित करता था। यही कारण है कि आज प्रदेश के कई खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के नए मॉडल उभर रहे हैं।

वर्तमान सरकार की चुनौती निरंतरता बनाए रखना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भले ही नई ऊर्जा और पहल के साथ आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उन्हें समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र की स्थिरता "नीति की निरंतरता" में छिपी होती है। अगर राजनीतिक स्वार्थ में पूर्ववर्ती नीतियों को खारिज किया जाएगा, तो निवेशक विश्वास डगमगा जाएगा। वर्तमान में राज्य को जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं, वे नीति के सतत प्रभाव का परिणाम हैं इसलिए इन नीतियों की निरंतरता बनाए रखना ही सबसे बड़ा प्रशासनिक निर्णय होगा।

नीति की सफलता, राजनीति से परे

कमलनाथ ने अपने अल्प कार्यकाल में जो आधारशिला रखी थी, वही आज प्रदेश की उपलब्धियों की नींव बन गई है। भाजपा सरकार को चाहिए कि इस नीति की सकारात्मक परंपरा को आगे बढ़ाए, न कि उसे केवल राजनीतिक दृष्टि से देखे। प्रदेश को आज नीतियों की राजनीति नहीं, बल्कि नीति की स्थिरता चाहिए। यदि कमलनाथ द्वारा बनाई गई पारदर्शी, निवेशक-उन्मुख और सामाजिक दृष्टि वाली नीति का सतत पालन हुआ, तो मध्यप्रदेश न केवल खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि "मिनरल हब ऑफ इंडिया" के रूप में अपनी पहचान को सशक्त करेगा।

विकास, विरासत और भविष्य की राह विकसित प्रदेश बनने की श्रेणी में अग्रसर मध्यप्रदेश

(पेज 2 का शेष)

उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने "लाड़ली लक्ष्मी", "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना", "लाड़ली बहना योजना" जैसी योजनाओं से सामाजिक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। मध्यप्रदेश को "टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया" कहा जाता है — यहाँ पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा और पेंच जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये न केवल जैव विविधता के केंद्र हैं, बल्कि राज्य की पारिस्थितिक पहचान भी हैं। फिर भी, वन विनाश, खनन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। आने वाले वर्षों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मध्यप्रदेश ने भारतीय राजनीति में कई दिग्गज नेता दिए — जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, अर्विंद मेनन, शंकरदयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण यादव, और शिवराज सिंह चौहान। राज्य की राजनीति में समय-समय पर सत्ता परिवर्तन हुआ, पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहीं। सुशासन की दृष्टि से ई-गवर्नेंस, पंचायती राज सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन में राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

70 वर्ष की यात्रा के बाद आज मध्यप्रदेश एक उभरते हुए विकासशील राज्य के रूप में खड़ा है। परंतु 21वीं सदी की चुनौतियाँ नई हैं जैसे रोजगार सृजन, जल प्रबंधन, शहरी भीड़ नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सतत विकास। राज्य को अब "विकास का हृदय" बनने के लिए नवाचार (Innovation), हरित ऊर्जा, डिजिटल शिक्षा, और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास की खाई को पाटना, और हर वर्ग तक विकास के लाभ पहुँचाना, आने वाले दशक की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मध्यप्रदेश की 70 वर्षों की यह यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, सहयोग और संकल्प की कहानी है। यह उस धरती की कहानी है जहाँ कालिदास ने "मेघदूत" लिखा, जहाँ सांची के स्तूपों में बौद्ध शांति का संदेश अंकित है, और जहाँ नर्मदा की धारा जीवन का प्रतीक है।

सम्पादकीय

बिहार चुनावः सत्ता की कशमकश

बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। 14 नवंबर को परिणाम आयेंगे। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं। सभी लोकलुभावन वादे किये हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जहां बेरोजगारी दर राज्य में 3-5.2% है, लेकिन युवा बेरोजगारी 26.4% तक पहुंच चुकी है। महागठबंधन ने 28 अक्टूबर को 'बिहार का तेजस्वी प्रण' जारी किया, जबकि एनडीए (बीजेपी-जेडीयू-अन्य) ने 31 अक्टूबर को 'संकल्प लॉन्च किया। दोनों ने रोजगार पर भारी वादे किए, लेकिन आलोचक इन्हें 'अफसाने' बता रहे हैं। क्योंकि पिछले चुनावों में समान वादे (जैसे 10 लाख नौकरियां) अधूरे रह गए थे। महागठबंधन का 'बिहार का तेजस्वी प्रण' युवाओं के लिए ढेर सारे वादे करता है तो जोक बनने लगे हैं। इसके अलावा सभी संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का वादा, जीविका दीदियों को 30,000 मासिक वेतन के साथ स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, बेरोजगारी भत्ता (ग्रेजुएट/डिप्लोमा धारकों के लिए), IT पार्क, SEZ, डेयरी/एग्रो इंडस्ट्री जैसे वादे किये गये हैं। बिहार में लगभग 2.5 करोड़ परिवार हैं। यदि न्यूनतम वेतन 18,000 मासिक मानें, तो सालाना खर्च 5.5 लाख करोड़ से अधिक होगा जो राज्य के 2025-26 के कुल बजट से दोगुना (3.16 लाख करोड़) है। वर्तमान में बिहार सरकार के पास मात्र 26.5 लाख कर्मचारी हैं।

बिहार में होने वाला चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक कवायद नहीं है, इसमें तीन दिग्गजों- नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति दांव पर लगी है। दो दल- जदयू और लोजपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि शक्तिशाली भाजपा और इंडिया का भंगुर गठबंधन सबसे कठिन लड़ाई में जूझने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच बार चुनाव जीता है, परंतु यह उनका निर्णायक चुनाव होगा। उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत 2010 के 22.6 फीसदी से घटकर 2020 में 15.7 प्रतिशत रह गया। बेरोजगारी बिहार की आत्मा से जुड़ी है और 75 लाख लोग बिहार से बाहर मेहनत कर जीविका चला रहे हैं। विस्थापन एक ऐसा घाव है, जो भरना ही नहीं चाहता। नीतीश कुमार को अपने दम पर बहुमत लाना होगा, ताकि एनडीए में अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाये रखें, जिसने उन्हें मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया है। इससे कुछ स्थानीय भाजपा नेता परेशान हैं, जो बड़ी भूमिका चाहते हैं।

बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका इन दिनों तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें लालू के बेटे से अलग पहचान साबित करनी होगी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी अपने मुस्लिम-यादव जनाधार पर निर्भर हैं, जिसके बूते 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीत राजद राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। एनडीए के मजबूत जातिगत समीकरण को चुनौती देने के लिए तेजस्वी को अब ओबीसी, दलितों और कमजोर तबकों तक पहुंच बनानी होगी। बिहार के रण में राहुल गांधी भी अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं। वर्ष 2020 में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस गठबंधन में जूनियर पार्टनर है, फिर भी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बड़ी है। यह चुनाव न केवल इस प्रांत में कांग्रेस की संभावनाओं की परीक्षा है, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में राहुल की नियति भी तय करेगा। तेजस्वी और कन्हैया कुमार के साथ राज्य पदयात्रा में उन्होंने उन मुद्दों को उभारा, जो युवाओं के मुद्दे हैं। यानी बेरोजगारी, विस्थापन और आर्थिक महत्वाकांक्षा। कांग्रेस के 'पलायन रोको, नौकरी दो' का नारा बिहार की हकीकत से जुड़ गया है, जहां के 51.2 फीसदी मतदाताओं ने रोजगार को अपनी प्रमुख प्राथमिकता बतायी है। बिहार की राजनीति अब भी जातिगत समीकरणों पर निर्भर है। एक सर्वे बताता है, 51.2 फीसदी मतदाताओं ने बेरोजगारी को, 45.7 प्रतिशत वोटरों ने मुद्रास्फीति को और 41 फीसदी वोटरों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है। पर जातिगत समीकरणों को, नीतीश द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों तथा चिराग द्वारा पासवान मतदाताओं, साधने के कौशल के कारण एनडीए अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी है।

सियासी गहमागहमी

प्रदेश के दो मंत्रियों से गरमाई राजनीति

भाजपा की प्रदेश राजनीति में इन दिनों हलचल तब तेज हो गई जब पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से लौटे दो प्रमुख मंत्रियों ने राज्य में सक्रियता बढ़ा दी। संगठन से लेकर सरकार तक उनके दौरों और बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र से लौटे इन मंत्रियों की सक्रियता केवल नियमित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आगामी चुनावी रणनीति या संगठनात्मक पुनर्संतुलन का संकेत भी हो सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब केंद्रीय नेतृत्व किसी राज्य के मंत्रियों या नेताओं पर विशेष ध्यान देता है, तो उसके पीछे संगठनात्मक पुनर्गठन या नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएँ चर्चा में आती हैं। प्रदेश भाजपा इस समय आगामी स्थानीय निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर पार्टी की नब्ज टटोलने और स्थानीय समीकरणों को साधने का प्रयास जारी है।

भूपेश बघेल और उनसे जुड़े अधिकारियों की बढ़ सकती है चिंता

छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न राज्योत्सव समारोह जहाँ एक ओर सांस्कृतिक उत्सव और विकास योजनाओं के प्रदर्शन का मंच बना, वहीं दूसरी ओर इसके राजनीतिक अर्थ भी तेजी से उभरने लगे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति में जो समीकरण बन रहे हैं, उनके बीच यह कार्यक्रम सरकार की ताक़त और जनसमर्थन का प्रदर्शन माना जा रहा है। राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल की भी अप्रत्यक्ष समीक्षा की। इसी संदर्भ में यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य सरकार जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण जांचों और प्रशासनिक पुनर्समीक्षा की दिशा में कदम उठा सकती है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके शासनकाल से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चिंता बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। वर्तमान सरकार ने संकेत दिए हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। इस क्रम में यदि पूर्व शासनकाल के निर्णयों या योजनाओं की जांच आरंभ होती है, तो यह राजनीतिक रूप से भी बड़ा संदेश देगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राज्योत्सव के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ सत्तारूढ़ दल इसे "सुधारात्मक कदम" बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे "राजनीतिक बदले की कार्रवाई" कह सकता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

कुछ दिनों पहले बिहार के युवाओं से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर मुद्दे पर। और, इन सबकी दुर्दशा के लिए सिर्फ एक गुनहगार है, BJP-JDU सरकार।

बिहार के युवा बखूबी जानते हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरह इस मोदी-नीतीश सरकार ने उनकी आकांक्षाओं का गला घोंटा है, प्रदेश को लावारिस छोड़ दिया है और हर पैमाने पर गर्त में धकेल दिया है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की सरकार की आमदनी और खर्च के बीच आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति आ गई है।

प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से 5200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके बाद प्रदेश के ऊपर कुल कर्ज की राशि अब 4.60 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपये है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भारत की स्वतंत्रता और जनकल्याण के लिए समर्पित रहे हैं दादाभाई नौरोजी

समता पाठक/जगत प्रवाह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को "भारत के वृद्ध पुरुष" कहे जाने वाले दादाभाई नौरोजी का जन्म मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक, नौरोजी का जीवन भारतीय इतिहास में अत्यंत प्रेरणादायक है। इस लेख में उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, शैक्षणिक करियर, व्यापारिक और राजनीतिक जीवन पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। दादाभाई नौरोजी का जन्म बॉम्बे (अब मुंबई) में एक गुजराती भाषी पारसी परिवार में हुआ था। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे और प्रारंभ से ही शिक्षा तथा समाज सेवा में रुचि रखते थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे से जुड़े। वर्ष 1855 में वे वहीं गणित और प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर बने। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय कॉलेज में गुजराती भाषा के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। इस प्रकार उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

दादाभाई नौरोजी केवल एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी व्यापारी भी थे। उन्होंने कामा एंड कंपनी नामक फर्म में साझेदार के रूप में कार्य किया। यह ब्रिटेन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं का कॉटन ट्रेडिंग व्यवसाय भी शुरू किया। उनका मानना था कि व्यापार और उद्योग के माध्यम से ही भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। नौरोजी का राजनीतिक जीवन वर्ष 1874 में प्रारंभ हुआ जब वे बड़ौदा राज्य के महाराजा के दीवान (प्रधान मंत्री) बने। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी, दक्षता और सुधारों के लिए ख्याति प्राप्त की। उन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर चर्चा करना था। इसके दो वर्ष बाद, 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था — ब्रिटिश जनता और संसद तक भारत की वास्तविक स्थिति और विचार पहुँचाना।

दादाभाई नौरोजी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस संगठन की स्थापना 1885 में दीनशॉ वाचा और ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर की गई थी। नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष तीन बार (1886, 1893, 1906) चुना गया। वे कांग्रेस के मध्यमपंथी धड़े के प्रमुख नेता थे, जो संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन में सुधार और भारतीयों के अधिकारों की माँग करते थे। दादाभाई नौरोजी भारतीयों के लिए इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आए जब वे 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। वे फिन्सबरी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। वे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर लगातार आवाज उठाई। नौरोजी ने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि समाज और धर्म के क्षेत्र में भी कार्य किया। उन्होंने 1851 में रहनुमा-ए-मजदयसने सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पारसी धर्म (जोरास्ट्रियनिज्म) को पुनर्जीवित और सशक्त बनाना था। यह संस्था आज भी मुंबई में सक्रिय है। दादाभाई नौरोजी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शक और प्रेरक माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपालकृष्ण गोखले जैसे नेताओं को दिशा दी। गांधी जी उन्हें "दादा भाई" कहकर सम्मानित करते थे। उनकी नीतियाँ और विचार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बौद्धिक आधार बने। नौरोजी का विश्वास था कि भारतीयों को अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा, एकता और तर्कपूर्ण संघर्ष का सहारा लेना चाहिए। दादाभाई नौरोजी का निधन 1917 में मुंबई में हुआ। उस समय उनकी आयु 91 वर्ष थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे भारत की स्वतंत्रता और जनकल्याण के लिए कार्य करते रहे।

1 नवंबर- मध्य प्रदेश स्थापना दिवस विशेष

मध्य प्रदेश: धरोहर, विकास और गौरव की धरती

भारत के मध्य में स्थित यह पावन भूभाग जब 1 नवंबर 1956 को "मध्य प्रदेश" नाम और स्वरूप में स्थापित हुआ, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रदेश आने वाले समय में संस्कृति, अध्यात्म, प्राकृतिक धरोहर और विकास का ऐसा जीवंत संगम बनेगा। आज मध्य प्रदेश केवल मानचित्र का केंद्र नहीं, भारतीयता का हृदय है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ की नर्मदा और यहाँ का मानव—सभी में एक सहज अपनापन है। यही कारण है कि हर मध्य प्रदेशवासी गर्व से कहता है—यह प्रदेश "Heart of India" ही नहीं, "Soul of India" भी है।

इतिहास, अध्यात्म और कालजयी विरासत

मध्य प्रदेश की हर धरा इतिहास की गाथा सुनाती है। सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे महावीरों के साहस तक—यह भूमि त्याग, पराक्रम और संस्कृति की प्रतीक है। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रगुफाएँ, साँची का स्तूप, मंदसौर का सूर्य मंदिर और भोजपुर का विशाल शिवालय—यह सिद्ध करते हैं कि यह प्रदेश सभ्यता का जनक और आस्था का आधार रहा है। और फिर उज्जैन... महाकाल की नगरी और ओम्कारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जहाँ हर श्वास में "हर-हर महादेव" गूँजता है। यह प्रदेश केवल विरासत नहीं, बल्कि सजीव संस्कार है।

प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन

सतपुड़ा की गोद, नर्मदा का आंचल और वन्य जीवन का अद्भुत संसार—मध्य प्रदेश प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना जैसा है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा के जंगलों में जीवन की धड़कनें सुनाई देती हैं। भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या इसी प्रदेश की शान है। भेड़ाघाट के संगमरमर, तवा के शांत जल, मांडू की बादल घाटी और पचमढ़ी के शांत शिखर—हर गंतव्य प्रकृति और इतिहास दोनों का उत्सव है। इसीलिए मध्य प्रदेश को कई बार 'बेस्ट टूरिज्म स्टेट' का सम्मान मिला है।

अर्थव्यवस्था और प्रगति का उभरता केंद्र

कृषि: सोयाबीन, दलहन एवं तिलहन उत्पादन में अग्रणी, कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित।

उद्योग और व्यापार: इंदौर स्वच्छता और स्टार्टअप्स का मॉडल; भोपाल—हरियाली एवं स्मार्ट सिटी विकास का उदाहरण।

ऊर्जा: रीवा का सोलर प्रोजेक्ट वैश्विक पहचान।

शिक्षा व स्वास्थ्य: निरंतर सुधार और नवाचार।

सड़क व बुनियादी ढाँचा: गाँव से शहर तक जुड़ता आधुनिक विकास।

संस्कृति, लोकजीवन और आत्मीयता

मध्य प्रदेश की पहचान उसके लोग हैं। यहाँ की भाषा में मिठास है, व्यवहार में नम्रता है और संबंधों में आत्मीयता।

पोहा-जलेबी से दाल-बाफला तक

मालवी, बघेली, निमाड़ी, बुंदेली सुरों से लेकर गोंड कला और भीली नृत्य तक—यह प्रदेश संस्कृति और जीवन का उत्सव है। यहाँ हर अतिथि का स्वागत स्नेह से होता है।

स्थापना दिवस: गर्व, चिंतन और संकल्प

मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस केवल इतिहास का स्मरण नहीं, भविष्य का संकल्प भी है। हमारा गर्व तभी सार्थक होगा जब हम अपने प्रदेश की पहचान में अपना योगदान जोड़ें। सिर्फ सरकारें प्रदेश नहीं बनातीं— जनता भी बनाती है। भविष्य की दिशा हमारे सामूहिक व्यवहार और दृष्टि से तय होती है।

हम मध्य प्रदेश हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है

प्रत्येक मध्य प्रदेशवासी का दायित्व है कि वह अपने प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने में अपना योगदान दे—

- स्वच्छता को आदत बनाएँ, केवल अभियान नहीं।
- युवाओं में शिक्षा, कौशल और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दें।
- पर्यटन स्थलों को संजोएँ, मार्गदर्शन और आतिथ्य को आदर्श बनाएँ।
- जनजातीय कला, लोकभाषाओं व स्थानीय शिल्पकारों को प्रोत्साहन दें।
- पर्यावरण व नदियों को बचाने का संकल्प लें—नर्मदा सिर्फ नदी नहीं, जीवन है।
- धैर्य, संवाद और सहयोग से सामाजिक सौहार्द को मजबूत करें।
- हर नागरिक अगर यह तय कर ले कि मुझे अपना प्रदेश आगे ले जाना है, तो कोई शक्ति मध्य प्रदेश को विश्व मानचित्र पर अग्रणी बनने से नहीं रोक सकती। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय मध्य प्रदेश। जय भारत।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छाशक्ति से लौहपुरुष बने सरदार पटेल: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छाशक्ति से लौहपुरुष बने। आजादी के बाद के कठिन हालातों में उन्होंने अपनी सूझबूझ और फौलादी इरादों से 562 रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। किसानों के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में यह बात कही। यह कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग

द्वारा रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनके महान योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि "सरदार पटेल ने अपनी विराट सोच और अटूट इच्छाशक्ति से टुकड़ों में बंटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया।" सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। उनकी 150वीं जयंती पर आज पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को भी आमंत्रित किया गया है, जहाँ राज्य का विशेष स्टॉल भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 'रन फॉर यूनिटी' केवल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह फिटनेस और सामूहिक ऊर्जा का भी संदेश देता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि "सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की आजादी और किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कठोर संघर्ष किया।" उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए ही उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को साकार किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए रंगोली और चित्रों का अवलोकन किया तथा उपस्थित जनों को स्वदेशी अपनाने और भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रन फॉर यूनिटी के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए रंगोली, चित्रकला, भाषण एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने रंगोली, चित्रकला, भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया तथा रन फॉर यूनिटी के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 'बस्तर ओलंपिक' के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाई। यह प्रचार रथ बस्तर संभाग के सभी जिलों में पहुंचकर बस्तर ओलंपिक का प्रचार-प्रसार करेगा।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को पूरे देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर तिनका सामाजिक संस्था द्वारा शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अन्य सभी विभागों के संयुक्त समन्वय से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक श्रीमती हिना अली ने बताया कि थाना प्रभारी मुकेश गौड़ के नेतृत्व में इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ, एनसीसी एवं एनएसएस कैडेट्स तथा स्थानीय जनसमुदाय ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 100 से अधिक खिलाड़ी दौड़ में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में रस्साकशी एवं कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतुल बारंगे सुनील दुबे सुधीर गौर अंकीत कनेरे सुनीत कशिव श्रीमती मोनिका चन्देल श्रीमती मोना खरे श्रीमती विजेता ओसवाल दिनेश सोनी हरिओम गौर नितेश कनाडे श्रीमती नंदनी अग्रवाल एवं राजेश नागरे उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय एकता अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने युवाओं से सरदार पटेल के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश की एकता एवं विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने "दिशा" की बैठक में उठाया अवैध गुमटियों सहित अतिक्रमण का मामला

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में आईटीआई रोड पर आरटीओ कार्यालय के सामने रातों-रात अवैध रूप से बड़ी संख्या में रखे गए टपों का विषय उठा है। नगर की मुख्य सड़कों पर भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण और हाथ ठेलों से यातायात अवरोध हो रहा है। नगर में निरंतर अतिक्रमण से जाम के हालात निर्मित होते हैं। बस स्टैंड के साथ आसपास के क्षेत्र में भी यही हालत है। सतरास्ते पर भी यही हालात हैं। जिससे आए दिन दुर्घटना और विवाद के हालात निर्मित होते हैं। नागरिक निरंतर नगर की सड़कों पर सुगम यातायात की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन की बैठकों में भी यह मुद्दा निरंतर प्रकाश में आ रहा है। दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने नगर में अवैध रूप से सड़क किनारे गुमटियां टप रखकर किए अतिक्रमण का विषय उठाया गया। जिससे यातायात अव्यवस्था से खराब हो रहे माहौल और अतिक्रमण से उत्पन्न हो रहे अवरोध को अवगत कराते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही किए जाने की बात रखी। दिशा की बैठक में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने अवगत कराया कि आईटीआई रोड पर शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज की दीवार से लगकर आरटीओ कार्यालय के सामने रातों-रात अवैध रूप से बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी के साथ वार्ड 15 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना की सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से अतिक्रमण होने से क्षेत्र

का माहौल खराब हो रहा है। इसी तरह ओवरब्रिज के नीचे भी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। मैंने एक पत्र भी दिया है कि शीघ्र अति शीघ्र अतिक्रमण हटाया जाए और कार्यवाही से मुझे अवगत कराया जावे। उल्लेखनीय कि पिछले करीब एक सप्ताह से आईटीआई रोड पर आरटीओ कार्यालय के सामने सड़क के दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नए टप रखे जा रहे हैं। यहां टप रखने की होड लगी हुई है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर सड़क किनारे किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर बेखौफ यहां अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है? जिसको लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। उसके बावजूद यहां से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा पाया है। पूर्व में आरटीओ द्वारा भी यहां पर अवैध रूप से संचालित टपों को हटाए जाने के लिए प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है। उसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, अब राज्यसभा सांसद द्वारा इस गंभीर मुद्दे को उठाया गया है।

बेटे ने की अपने माता-पिता की हत्या

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. सागर। जिले के देवरी थाना अंतर्गत एक छोटे से ग्राम में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम के पास स्थित नेशनल हाईवे के किनारे रहने वाले गणेश सेन और उनकी पत्नी का शव उनके ही घर से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही बेटे ने दिया है। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और हत्या के पीछे की असली वजह का जल्द खुलासा किया जाएगा।

सितंबर में भी सैलाब का सितम

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। यह हमें जल, वायु, भोजन, आवास और ऊर्जा जैसे अनमोल संसाधन प्रदान करती है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व तभी संभव है जब हम अपनी इस मातृ सत्ता प्रकृति का आदर करें और उसके साथ संतुलन बनाकर चलें। वर्तमान में व्याप्त सभी प्रकार की समस्याओं , पीड़ाओं और अभावों का मूल कारण प्रकृति के प्रति हमारी खुदगर्जी भरी विकारी मनोवृति है। इस बात को भले ही कोई प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार नहीं करें लेकिन सत्य यही है। पंच तत्वों से निर्मित जीवों का सर्वोपरि धर्म प्रकृति की रक्षा के लिए सर्वोत्तम है। किंतु आधुनिक युग में मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति का निरंतर दोहन किया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन और समाज में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव पुनः जागृत करें। प्रकृति का स्वरूप और उसका महत्व प्रकृति केवल पेड़-पौधों या नदियों का नाम नहीं है, यह संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें मनुष्य, पशु-पक्षी, जल, मृदा और वायुमंडल सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व की नींव को सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो यह केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं है, बल्कि यह वर्षा चक्र, मृदा की उर्वरता और जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य और प्रकृति का असंतुलन औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्य ने प्रकृति को अपनी अथीनस्थ वस्तु समझ लिया। शहरों का विस्तार, खनन, जंगलों की कटाई, रासायनिक खेती और प्रदूषणकारी उद्योगों ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसी विपदाएँ बढ़ रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो रहा है। यह सब हमारी असंवेदनशीलता का परिणाम है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति का आदर भारत में प्राचीन काल से प्रकृति को देवत्व का स्थान दिया गया है। वेदों में नदियों, पर्वतों, वृक्षों और वायु की स्तुति की गई है। हमारे पर्व जैसे वट सावित्री, तुलसी पूजन, गंगा दशहरा और छठ पूजा इस बात का प्रतीक हैं कि हम प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने की परंपरा रखते हैं। यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रकृति का उपयोग नहीं बल्कि संरक्षण ही सच्चा धर्म है। वर्तमान समय की चुनौतियाँ आज पृथ्वी वैश्विक तापमान वृद्धि और प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रही है। पृथ्वी का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे हिमनद पिघलने, समुद्री स्तर बढ़ने और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएँ घट रही हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए यह और चुनौतीपूर्ण है। बढ़ता शहरीकरण और अनियंत्रित औद्योगिकीकरण पर्यावरण को निरंतर चोट पहुँचा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी है। समाधान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रकृति का सम्मान केवल सरकार या संस्थाओं का नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कदम उठाकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पेड़ लगाना और पौधों की देखभाल करना। प्लास्टिक के उपयोग से बचना और पुनर्चक्रण को अपनाना। जल का अपव्यय रोकना तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाना, जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग।बच्चों में पर्यावरणीय चेतना का विकास करना। इसके साथ ही, सरकार को भी ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित हों। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के सख्त मानक लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और वन संपदा की रक्षा करना अनिवार्य है।निष्कर्षप्रकृति का सम्मान करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की शर्त है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी वह हमारी रक्षा करेगी। मानव सभ्यता का भविष्य उसी संतुलन में सुरक्षित है जो हमने अपने पर्यावरण के साथ स्थापित किया है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना ही इस संकट से निकलने का आधार बन सकती है। इसलिए आइए, हम सभी संकल्प लें कि प्रकृति के साथ विरोध नहीं, सहयोग में जीवन जिएँ। समय आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन संवर्धन के चिंतन को हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखें और इस क्षेत्र में पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य से जुटते हुए परिवर्तन लाएं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

(पेज 1 का शेष)

ऊर्जा उत्पादन में तेजी से प्रगति

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहाँ लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन में तेजी से प्रगति कर रहा है। अभी हम विद्युत उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हैं। राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 30 हजार मेगावॉट है और वर्ष 2030 तक यह क्षमता देश में प्रथम स्थान पर पहुँच जाएगी। छत्तीसगढ़ तेजी से सोलर क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सर्वाधिक लोकप्रिय योजना बन गई है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर इसका लाभ उठाने लगे है। वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल के माध्यम से मुफ्त बिजली की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार के नए अवसर भी सृजित

छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट और इंटीरियर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। राजधानी रायपुर, नया रायपुर और भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में 50 लाख आबादी की जरूरतें पूरी करेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। धान के साथ-साथ कोदो, कुटकी, रागी जैसी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई पम्पों को निःशुल्क बिजली की उपलब्धता एवं कृषि कल्याण के अन्य कार्यक्रमों से किसान सशक्त हो रहे हैं। लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इससे न केवल वनवासियों की आय बढ़ी है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।

कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले

बीते डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दूरस्थ इलाकों में स्कूल, मोबाइल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। बच्चों और युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने सुशासन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई है। ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से नागरिक घर बैठे राजस्व, पेंशन और प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं। कल्चर पार्क और फिल्म सिटी की स्थापना की पहल के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। खेलों के क्षेत्र में नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्रों का विकास युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहा है।

आत्मनिर्भर राज्यों में शामिल करना है

छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है। सड़क, रेल, उद्योग, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा-स्वास्थ्य, सुशासन और सांस्कृतिक सहित हर क्षेत्र में संतुलित विकास हो रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से ही संभव हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प 2047 तक राज्य को देश के अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्यों में शामिल करना है।

रसायन मुक्त खेती की ओर किसानों हो रहे हैं प्रेरित

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में पहचान मिला है, जिसमें कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों का प्रमुख योगदान रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषकों के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कृषक हितैशी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पी.एम किसान सम्मान निधि व कृषक उन्नति योजनाओं के द्वारा कृषकों को आर्थिक लाभ एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा आकस्मिक वर्षा एवं अन्य आपदाओं से हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति तथा वर्षा जल संरक्षण एवं उपलब्ध सिंचाई जल का समुचित एवं संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना तथा पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं संचालित की जा रही है। ड्रोन दीदी अभियान चला कर उर्वरक की कमी के समाधान हेतु नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पी.एम. प्रणाम कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने तथा जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना तथा जैविक खेती के माध्यम से रसायन मुक्त खेती की ओर किसानों को प्रेरित ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

किसानों की आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मुहईया कराई जा रही है तथा कृषको द्वारा उपार्जित धान के समुचित उपार्जन तथा उचित मूल्य हेतु समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन की व्यवस्था की गई है। यहां पर धान उपार्जन का मूल्य देश के अन्य राज्यों के तुलना में अधिक है। उपरोक्त समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों के कारण राज्य में कृषि के स्तर एवं किसानों के आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिसमें राज्य एवं केन्द्र शासन की कृषक कल्याणकारी योजनाओं का प्रमुख योगदान है।

6727 हजार हेक्टेयर में क्षेत्राच्छादन

प्रदेश में क्षेत्राच्छादन की दृष्टि से देखा जाय तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल 5408 हजार हेक्ट. था। वर्तमान 2025 में 6727 हजार हेक्ट. क्षेत्रफल हो गया है, जिसमें खरीफ फसलों का क्षेत्राच्छादन 4636 हजार हेक्टयर, जो वर्तमान में 4865 हजार हेक्ट. का क्षेत्राच्छादन विस्तारित हुआ है। धान फसल के क्षेत्राच्छादन 3795 हजार हेक्ट से बढ़कर 3981 हजार हेक्ट. हो गया है। दलहन का क्षेत्रफल भी 238 हजार हेक्ट. से बढ़कर 260 हजार हेक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार रबी फसलों में 772 हजार हेक्ट. से बढ़कर 1862 हजार हेक्ट. हो गया है। खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर राज्य ने खनिज प्रशासन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनन राज्यों में सम्मिलित हो गया है। राज्य में विश्वस्तरीय लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, टिन अयस्क सहित नवीन अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक तथा रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता प्रमाणित हुई है, जिससे राज्य की वैश्विक पहचान सुदृढ़ हुई है। छत्तीसगढ़ का खनन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि देश के कुल खनिज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है। राज्य के खनिज राजस्व में 25 सालों में 34 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के समय जहाँ खनिज राजस्व मात्र 429 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 14,592 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह उपलब्धि राज्य की सुदृढ़ खनिज नीति और सतत प्रशासनिक सुधारों का परिणाम है।

नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है

वर्ष 2015 में संशोधित खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित खनिज नीलामी नियम 2015 के तहत अब तक राज्य में 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें 15 लौह अयस्क, 14 बाक्साइट, 18 चूना पत्थर तथा 13 क्रिटिकल व स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉक सम्मिलित हैं। साथ ही, 05 नए ब्लॉकों (02 चूना पत्थर, 01 लौह अयस्क, 01 स्वर्ण और 01 बेस मेटल ब्लॉक) की नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है।

श्रम क्षेत्र में मिली विशिष्ट उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 16 जिलों में से 09 जिलों में श्रम कार्यालय तथा 04 जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय संचालित है। वर्तमान में राज्य के समस्त 33 जिलों में श्रम कार्यालय तथा 10 जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा वर्ष 2008 से रायपुर में इंडस्ट्रीयल हाईजिन लैब का राज्य स्तरीय कार्यालय प्रारंभ किया गया है। राज्य स्थापना के बाद से वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है। उक्त मण्डलों में श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभिन्न योजनाओं में आवेदन विभागीय पोर्टल/श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन करने की सुविधा दी गयी है तथा विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ते कदम

25 वर्ष की अवधि में बस्तर जिले के अंतर्गत किसानों को सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सकारात्मक प्रयास किया गया है। जिसके फलस्वरूप अब तक कुल 92 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 32 हजार 656 हेक्टेयर सिंचित रकबे का सृजन किया गया है। बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व 38 लघु सिंचाई योजनाओं से 7521 हेक्टेयर खरीफ एवं 1386 हेक्टेयर रबी कुल 8907 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हो रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद किसानों को खेती-किसानी के लिए ज्यादा से ज्यादा सिंचाई साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में 54 सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर 23 हजार 749 हेक्टेयर सिंचित रकबा का सृजन किया गया है। जिसमें 18 हजार 129 हेक्टेयर खरीफ और 5620 हेक्टेयर रबी फसल हेतु सिंचाई क्षेत्र विकसित किया गया है। इन सभी सिंचाई संसाधनों के माध्यम से क्षेत्र के किसानों द्वारा द्विफसलीय खेती-किसानी को बढ़ावा देकर आय संवृद्धि किया जा रहा है।

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं

उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रदेश के कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जीकृत करने का अभियान

नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध होता मध्यप्रदेश

व्यापक निवेश अवसर

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
- ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
- 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
- किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

- सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
- परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
- 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता सौर परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
- पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
- वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
- वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
- परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
- Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

RO No. D19201/25

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)